कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार

इरान-ईराक तनाव के कारण वेस्ट टेक्सास और ब्रेंट क्रूड बढ़े

1970 और 1979 के तेल संकट जैसी स्थिति दोहराने की आशंका

नई दिल्ली, 9 मार्च. तेल की दुनिया में फिर से हलचल मची है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं. ईरान से जुड़े संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति में बाधा के कारण वैश्विक बाजारों में तेजी से अस्थिरता देखी जा रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि यह ईरान के परमाणु खतरे का सामना करने की अस्थायी कीमत है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत 109.75 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड की कीमत 109.48 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह तनाव लंबा खिंचता है तो कीमतें और बढ़ सकती हैं. वैश्विक वित्तीय बाजारों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है. एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि तेल टैंकरों की आवाजाही काफी धीमी हो गई है. इतिहास बताता है कि फारस की खाड़ी में तेल संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. 1973 के अरब तेल प्रतिबंध और 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान भी तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और कई देशों में महंगाई और आर्थिक मंदी आई.

तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं

इस संकट का असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है. एशियाई बाजारों में कारोबार शुरू होते ही शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखी गई. जापान का बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 5 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का बाजार 7 प्रतिशत से अधिक गिर गया. विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. कुछ अनुमानों के अनुसार, इस साल के अंत तक कच्चा तेल 143 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है.

अकासा ने बिना शुल्क टिकट रद्द कराने की छूट 31 मार्च तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 09 मार्च. नवोदित विमान सेवा कंपनी अकासा एयर ने पश्चिम एशिया संकट के बीच बिना शुल्क टिकट रद्द कराने और यात्रा की तारीख में बदलाव का लाभ 31 मार्च तक की बुकिंग पर देने की घोषणा की है. अकासा ने सोमवार को जारी अपडेट में बताया कि यात्री प्रभावित मार्गों पर 31 मार्च 2026 तक की यात्रा की बुकिंग के लिए बिना किसी शुल्क के टिकट रद्द करा सकते हैं या यात्रा की तारीख में बदलाव कर सकते हैं.

एयरलाइन ने बताया कि सुरक्षा स्थिति के समीक्षा के बाद अकासा ने 31 मार्च तक अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और कोझिकोड से सऊदी अरब के शहर जेद्दा की उड़ानों के परिचालन का निर्णय लिया है.

सुंदर को मिलेगा 6361 करोड़ का पैकेज

गौरतलब है कि सुंदर पिचाई ने 2015 में गूगल के सीईओ का पद संभाला था. तब से कंपनी का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ चुका है. उनकी अगुवाई में कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और अन्य नई तकनीकों में तेजी से विस्तार किया है, जिससे कंपनी की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है.

नई दिल्ली, 9 मार्च. दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल के सीईओ सुन्दर पिचाई के वेतन पैकेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. कंपनी की मूल कंपनी अल्फाबेट ने अगले तीन वर्षों के लिए उनका कुल संभावित पैकेज बढ़ाकर 692 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,361 करोड़ रुपये कर दिया है.

इस बड़े पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष कॉरपोरेट प्रमुखों में शामिल हो गए हैं. अमेरिकी शेयर बाजार नियामक में दायर दस्तावेजों के अनुसार, इस पैकेज का बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. इसका मतलब है कि पिचाई की अंतिम कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अपने शेयरधारकों को कितना बेहतर रिटर्न देती है. इसके अलावा उन्हें स्टॉक इंसेंटिव, प्रतिबंधित शेयर और वार्षिक वेतन भी मिलेगा. कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स जैसे सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी और ड्रोन डिलीवरी बिजनेस से जुड़े प्रदर्शन के आधार पर भी उनके पैकेज में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है. दुनिया की प्रमुख टेक कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के वेतन पैकेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. कंपनी की मूल कंपनी. ने अगले तीन वर्षों के लिए उनका कुल संभावित पैकेज बढ़ाकर 692 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,361 करोड़ रुपये कर दिया है. इस भारी-भरकम पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉरपोरेट प्रमुखों में शामिल हो गए हैं. अगर कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो यह राशि बढ़कर 252 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन की स्थिति में यह भुगतान शून्य भी हो सकता है. इसके अलावा पिचाई को अगले तीन वर्षों में लगभग 84 मिलियन डॉलर के प्रतिबंधित शेयर भी दिए जाएंगे, जो उनके कंपनी में बने रहने की शर्त पर धीरे-धीरे जारी किए जाएंगे.

डिफेंस शेयरों में बड़ी गिरावट

मुंबई,09 मार्च. भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट का असर अब डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर भी दिखाई देने लगा है. सोमवार को कई प्रमुख रक्षा कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली, जिससे उनके दाम 6 प्रतिशत तक गिर गए.

बाजार में बने नकारात्मक माहौल और वैश्विक तनाव के कारण निवेशकों का रुख फिलहाल सतर्क नजर आ रहा है. कारोबार के दौरान डिफेंस सेक्टर के प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बाजार में बनी अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी है. हालांकि बाजार के जानकारों का कहना है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद डिफेंस सेक्टर की लंबी अवधि की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं. सरकार की बढ़ती रक्षा खर्च योजनाएं और कंपनियों के पास मौजूद बड़े ऑर्डर बुक इस सेक्टर को भविष्य में मजबूती दे सकते हैं. भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को आई गिरावट का असर डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर भी साफ दिखाई दिया. कारोबार के दौरान कई प्रमुख रक्षा कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली और कुछ स्टॉक्स में 6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.

बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की बदलती रणनीति का असर है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे निवेशकों ने मुनाफावसूली का रास्ता अपनाया है.

एसबीआई के शेयरों में भारी गिरावट- वैश्विक तनाव और शेयर बाजार में बिकवाली के बीच एसबीआई सहित कई बैंकिंग शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को आई भारी गिरावट का असर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर भी साफ दिखाई दिया. बाजार में तेज बिकवाली के चलते बैंक के शेयर करीब 7 प्रतिशत तक टूट गए, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा. दिन के कारोबार के दौरान एसबीआई का शेयर गिरकर 1064.30 रुपये के इंट्रा-डे लो स्तर पर पहुंच गया. इस गिरावट का सीधा असर बैंक के बाजार पूंजीकरण पर भी पड़ा और कुछ ही घंटों में निवेशकों की करीब 62 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति घट गई.

सोने-चांदी के दाम में आया उछाल

2210 रुपए उछली चांदी

817 रुपए महंगा हुआ सोना

नई दिल्ली, 9 मार्च. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली. ताजा आंकड़ों के अनुसार सोने के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतों को समर्थन मिल रहा है. ताजा रेट के अनुसार 999 शुद्धता वाला सोना करीब 817 रुपये महंगा होकर 1,59,568 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. इससे पहले शुक्रवार को इसका भाव 1,58,751 रुपये था. इसी तरह 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत भी बढ़कर 1,58,929 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं चांदी की कीमत में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है. एक किलो चांदी का भाव बढ़कर 2,62,803 रुपये हो गया है.

आंकड़ों के अनुसार 999 शुद्धता वाला सोना 817 रुपये की तेजी के साथ 1,59,568 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 1,58,751 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इसी तरह 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत भी बढ़कर 1,58,929 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 814 रुपये ज्यादा है.

शुगर कंपनियों की चांदी

बाजार में शेयर 11 प्रतिशत तक उछले

नई दिल्ली, 9 मार्च. नई दिल्ली में सोमवार को शुगर सेक्टर ने निवेशकों को खुश कर दिया. घरेलू शेयर बाजार में आम तौर पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन राणा शुगर्स, धामपुर शुगर मिल्स, डालमिया भारत शुगर, द्वारिकेश शुगर और बजाज हिन्दुस्तान जैसे कंपनियों के शेयरों ने तेजी दिखाई.

ये शेयर 8 प्रतिशत से लेकर 11 प्रतिशत तक उछल गए. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी के पीछे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की बढ़ती कीमतें हैं. जब तेल महंगा होता है, तो एथनॉल प्रोडक्शन के लिए गन्ने का डायवर्शन बढ़ जाता है. भारत में एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत पेट्रोल में तय प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाता है, जिससे किसानों और शुगर सेक्टर को फायदा मिलता है. क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें एथनॉल को फ्यूल सप्लायर्स के लिए आकर्षक बनाती हैं. इससे शुगर मिल्स गन्ने का एक बड़ा हिस्सा एथनॉल प्रोडक्शन की तरफ डायवर्ट करती हैं. इस वजह से शुगर सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत होती है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है. घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को आम तौर पर गिरावट के बावजूद शुगर सेक्टर ने निवेशकों को खुश कर दिया. राणा शुगर्स लिमिटेड, धामपुर शुगर मिल्स, डालमिया भारत शुगर, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज, श्री रेणुका शुगर्स और बजाज हिन्दुस्तान शुगर के शेयरों में 8 प्रतिशत से लेकर 11प्रतिशत तक की तेजी देखी गई.

स्पेस-ड्रोन स्टार्टअप में दीपिंदर गोयल की बड़ी एंट्री

नई दिल्ली,9 मार्च. भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सिर्फ फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स और फिनटेक तक सीमित नहीं रहा. अब निवेशकों की नजर डीपटेक, स्पेस टेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों पर तेजी से टिक रही है. इसी कड़ी में ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल एक और बड़ी टेक पहल में निवेश करने की तैयारी में हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक गोयल लखनऊ स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कलाम लैब्स में करीब 10 लाख डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ रुपये निवेश करने के एडवांस्ड स्टेज में हैं. सूत्रों के अनुसार यह निवेश 50 से 70 मिलियन डॉलर के बड़े फंड रेजिंग राउंड का हिस्सा होगा, जिसमें कई वैश्विक निवेशक भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

चावल, चीनी मजबूत, गेहूं नरम, दालों, खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 09 मार्च. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी में तेजी रही, जबकि गेहूं में नरमी देखी गयी. दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 103 रुपये बढ़कर 3,856 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 44 रुपये टूटकर 2,810 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. आटा भी 62 रुपये सस्ता हुआ. दाल-दलहनों में तुअर दाल औसतन 161 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

ऑटो इंडस्ट्री मुश्किल में, बिक्री में गिरावट

मेमोरी चिप की कमी से कार कंपनियों की बढ़ी चिंता

चीन-अमेरिका-यूरोप में गिरी कार बिक्री, बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली, 09 मार्च. दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन दिनों कई मोर्चों पर दबाव का सामना कर रही है. मांग में गिरावट, बढ़ते टैरिफ, कच्चे माल की महंगी कीमतें और सप्लाई चेन में लगातार आ रही दिक्कतों ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है.

अब इन चुनौतियों के बीच मेमोरी चिप की कमी भी एक नई समस्या बनकर सामने आई है, जिसका सीधा असर वाहनों के उत्पादन और बिक्री पर पड़ रहा है. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में वैश्विक पैसेंजर व्हीकल बिक्री में मामूली बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन 2026 की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. साल की शुरुआत में ही प्रमुख बाजारों—चीन, अमेरिका और यूरोप—में वाहन बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. खासतौर पर चीन में सरकारी सब्सिडी खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पर असर पड़ा है.

एयर कंडीशनर की कीमतों में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि

नई दिल्ली, 09 मार्च. की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में मई-जून जैसी गर्मी महसूस होने लग्गी है. तापमान बढ़ने के साथ एयर कंडीशनर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

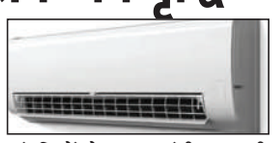

जिन घरों में एसी नहीं है, वे लोग नया एसी खरीदने की योजना बना रहे हैं, जबकि कई परिवार अतिरिक्त एसी लगाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच उपभोक्ताओं के लिए एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. देश की कई बड़ी एसी निर्माता कंपनियों ने एयर कंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक कंपनियां फरवरी से अप्रैल के बीच अपने एसी मॉडल्स की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक इजाफा कर रही हैं. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की जा रही है जब गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है और बाजार में एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है.

समाचार विशेष

ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली से बंगाल फतह की तैयारी

अल्पसंख्यक गणित के बीच भाजपा की नई रणनीति तैयार

कोलकाता. 14 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने जा रही है और इसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अगले राजनीतिक अभियान की शुरुआत माना जा रहा है. पार्टी 2019 और 2021 में मिले राजनीतिक विस्तार को और मजबूत करने की रणनीति बना रही है, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग हैं.

एक तरफ वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बड़ा फैक्टर बना हुआ है. बीजेपी की कोशिश है कि वह विकास और कल्याण योजनाओं के बड़े पैकेज का वादा कर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की नकद सहायता योजनाओं को चुनौती दे सके.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता के उदाहरण लोगों के सामने हैं और इससे भरोसा बनता है कि बीजेपी अपने वादे पूरे करती है. हालांकि इस बार पार्टी हर सीट पर पूरी ताकत झोंकने के बजाय ज्यादा रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है. बीजेपी मानती है कि राज्य में अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती है, इसलिए पार्टी का फोकस उन इलाकों पर रहेगा जहां हिंदू वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

बीजेपी का अगले चरण का लॉन्चपैड- प्रधानमंत्री की यह रैली पूरे राज्य में निकाली गई नौ परिवर्तन यात्राओं के बाद हो रही है और इसे बंगाल में राजनीतिक लामबंदी के अगले चरण का लॉन्चपैड माना जा रहा है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2021 को इसी मैदान में रैली की थी, जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी थी. तब से पार्टी लगातार यह समीक्षा कर रही है कि क्या काम आया और क्या नहीं.

बीजेपी के लिए क्या है चुनौती?

बीजेपी की आंतरिक राजनीतिक समीक्षा के मुताबिक राज्य को तीन बड़े चुनावी जोनों में देखा जा रहा है. पहला उत्तरी इलाका है जिसमें दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जैसे जिले आते हैं. यहां चाय बागान मजदूरों, राजबंशी और अन्य समुदायों के बीच बीजेपी ने धीरे-धीरे अपना आधार मजबूत किया है. दूसरा केंद्रीय बेल्ट है जो पुरुलिया से लेकर हावड़ा-हुगली तक फैला है. इसमें मेदिनीपुर और बर्धमान जैसे इलाके शामिल हैं जहां पिछले दो चुनावों में बीजेपी का समर्थन बढ़ा है.

मिशन 2027 में जुटे सीएम योगी

मेरठ में आरएसएस पदाधिकारियों के साथ की बैठक

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कवायद तेज होती दिख रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में सरकार के कामकाज पर जमीनी प्रतिक्रिया ली गई और चुनावों की पृष्ठभूमि में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं के प्रभाव, स्थानीय समस्याओं और संगठन के सुझावों को सीधे समझना था, ताकि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सुधार किए जा सकें. इसे 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मेरठ प्रांत में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल शामिल हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसे बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. बैठक में इन इलाकों से तीन दर्जन से अधिक संघ पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के कार्यों को लेकर संघ पदाधिकारियों से सीधे प्रतिक्रिया ली. पदाधिकारियों ने विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अपनी राय साझा की.

पिनाराई के विज्ञापन ने मचाया बवाल

सरकार की प्रशंसा करने वाले विज्ञापन पर विवाद गहराया

तिरुवनंतपुरम. केरल सरकार द्वारा मार्च 2026 में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जारी इरुंडा कालम (अंधकार युग) विज्ञापनों ने विवाद खड़ा कर दिया है. इन विज्ञापनों में पिछली यूडीएफ सरकार की कथित प्रशासनिक विफलताओं की तुलना वर्तमान एलडीएफ सरकार की उपलब्धियों से की गई है. समाचार रिपोर्ट की शैली में तैयार इन विज्ञापनों में बिजली की कमी और स्कूलों के बंद होने जैसे मुद्दों को उठाया गया है, जबकि बुनियादी ढांचे और शिक्षा में हुई प्रगति का गुणगान किया गया है. विपक्ष ने सरकारी खर्चे पर जारी इस विज्ञापन का कड़ा विरोध किया है.

विज्ञापन का पहला पन्ना दस साल पहले मलयालम अखबारों में छाई खबरें कैप्शन के साथ तैयार किया गया है. इसे इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि यदि वर्तमान में यूडीएफ सत्ता में होती, तो अखबार का फ्रंट पेज कैसा दिखता. इसकी मुख्य हेडलाइंस (सुर्खियों) में शामिल हैं. इसके अलावा, फ्रंट पेज पर ऐसी काल्पनिक रिपोर्ट दिखाई गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि 40 प्रतिशत स्कूल बंद होने वाले हैं, छात्र बिना किताबों के परीक्षा दे रहे हैं, गेल पाइपलाइन परियोजना अटकी हुई है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विकास कार्य रोक दिया है और भुगतान न होने के कारण सड़कों का काम ठप पड़ा है. विज्ञापन के दूसरे पन्ने पर इन्हीं कहानियों का सकारात्मक पक्ष पेश किया गया है, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि पहले पन्ने पर बताई गई सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है. विज्ञापन में एक कैप्शन दिया गया है जिसमें दावा किया गया है कि यह इस बात का सच्चा प्रतिबिंब है कि कैसे पहली और दूसरी पिनाराई सरकार ने केरल को सुधारा है.

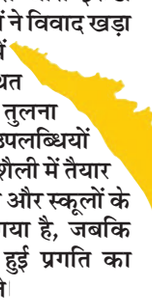

विशेष क्या यूपी चुनाव 2027 में अखिलेश यादव का दांव होगा सफल

पीडीए फार्मूला फिर से आजमाने की तैयारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत का समीकरण कभी भी स्थायी नहीं रहा है. हर बार के चुनाव में कुछ अलग समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी होती है.

हालांकि, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी चुनाव 2027 में एक बार फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, सपा अध्यक्ष इस बार पिछड़ा के साथद्ध अगड़ा को साधने का भी प्रयास करते दिख रहे हैं. उनकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को ध्वस्त करने की है.

दरअसल, यूपी चुनाव 2027 विपक्षी दलों के लिए अहम है. 2014 में यूपी की

राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही विपक्षी दलों की तमाम रणनीति बिखर गई. समाजवादी पार्टी प्रदेश में माय (मुस्लिम + यादव) समीकरण के साथ दमदार प्रदर्शन करती रही थी. 2012 के विधानसभा चुनाव में इस समीकरण ने पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया था. वहीं, बसपा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक राजनीति में गहरी पैठ बना रखी थी. लेकिन, ये सभी समीकरण धराशायी हो गए.

10 साल बाद बदली स्थिति- यूपी में करीब एक दशक तक राजनीतिक समीकरण नहीं बदले. इसके पीछे नरेंद्र मोदी की दमदार लीडरशिप और उनके स्तर पर लिए गए फैसले रहे. 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद विपक्षी दलों ने भले ही पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया. फैसले पर सवाल उठाए गए. लेकिन, यूपी की जनता को यह फैसला पसंद आया. यही वजह रही कि तीन माह बाद प्रदेश में सपा-बसपा को साफ करते हुए भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की.

नई राजनीति को आजमाने की तैयारी

समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के काल से ही यादव और मुसलमानों की पार्टी समझी जाती रही थी. उनके निधन के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की इस छवि को तोड़ने का प्रयास किया. पार्टी लोकसभा 2014 और 2019 में पांच-पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी. ऐसे में पार्टी ने जातीय समीकरणों के हिसाब से पिछड़े और दलित समाज के उम्मीदवारों को टिकट बांटे. मुस्लिम और यादवों को उस लिहाज से टिकट नहीं दिए गए. लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की. समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस को भी गठबंधन का लाभ मिला. 2014 और 2019 में दो एवं एक सीट जीतने वाली कांग्रेस ने इस चुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज की.